उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–08(10/56)

उत्तराखण्ड निवेश के लिए आदर्श राज्य : केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह

- इन्वेस्टर्स समिट में कुल 1 लाख 20 हजार 150 करोड़ रूपए के एमओयू।
- विभिन्न क्षेत्रों में 601 एमओयू किए गए।
- दो दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रधानमंत्री सहित सभी प्रतिभागियों का आभार जताया।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के लिए राज्य सरकार को बधाई देते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर पर निवेशक सम्मेलन का सफलता पूर्वक आयोजन काबिलेतारीफ है। जैसे पृथ्वी शॉ ने शतक लगाकर शानदार शुरूआत की वैसे ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निवेशक सम्मेलन द्वारा उत्तराखण्ड में विकास की शानदार शुरूआत की है।

केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अर्थव्यवस्था किसी भी देश व प्रदेश की रीढ़ होती है। इसे मजबूत करने के लिए अधिकतम निवेश की जरूरत होती है। उत्तराखण्ड में पर्याप्त प्राकृतिक व मानव संसाधन हैं। स्थायी सरकार है। निवेश के लिए सबसे बड़ी जरूरत बेहतर कानून व्यवस्था होती है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्तराखण्ड आदर्श राज्य है। यहां पर्यटन, एरोमा, योग, आयुश व वैलनैस की काफी सम्भावनाएं हैं। इनमें दुनियाभर से लोग यहां आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने इसे स्पीरीचुअल इको जोन ठीक कहा है। यहां के वातावरण में विशेष प्रकार की स्पिरीचुअल वाईब्रेशन है। उत्तराखण्ड के लोग बड़े मन के हैं। मन का बड़ा होना ही अध्यात्म है। राज्य सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, उससे रिवर्स माईग्रेशन जल्द ही प्रारम्भ होगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में अनेक बड़े संरचनात्मक परिवर्तन किए गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि 2030 तक भारत दुनिया की टॉप तीन अर्थव्यस्थाओं में आ जाएगा। यहां आर्थिक अवसरों की विविधता दुनिया में सबसे ज्यादा है। जीएसटी भारत के लिए वरदान साबित होने जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इंवेस्टर्स समिट में उद्यमियों व निवेशकों से उम्मीद से बढ़कर रेस्पोंस मिला है। कुल मिलाकर 601 एमओयू हुए हैं। 1 लाख 20 हजार करोड़ रूपए से अधिक का एमओयू हुआ है। इस माह में और भी निवेशकों के प्रस्ताव मिलने वाले हैं। इन्वेस्टर्स समिट द्वारा प्रदेश के विकास का लान्चिंग पैड तैयार हो चुका है। वर्ष 2025 में उत्तराखण्ड का अलग स्वरूप होगा। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक खुशहाल उत्तराखण्ड बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने कन्ट्री पार्टनर जापान व चेक गणराज्य के राजदूतों का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने सिंगापुर के सूचना प्रसारण मंत्री का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में प्रतिभाग करने आए उद्यमियों, निवेशकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सफल आयोजन के लिए इससे जुड़े सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को बधाई दी।

उत्तराखण्ड के वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 अटल बिहारी वाजपेयी ने न केवल उत्तराखण्ड का निर्माण किया था बल्कि इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया और विशेष औद्योगिक पैकेज दिया। अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर औद्योगिक विकास का धरातल तैयार किया है। हम पूंजी निवेश के लिए जो वातावरण बना रहे हैं वो कहीं और नहीं मिल सकता है।

रसना प्राईवेट लिमिटेड के चेयरमैन पिरूज खमबटा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री रावत ने एक चुम्बक की तरह निवेशकों को आकर्षित किया। उन्होंने अहमदाबाद में रोड़ शो के दौरान जिस प्रकार पक्ष रखा उससे हमें लगा कि अगर इन्वेस्टर्स समिट में शामिल नहीं हुए तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इससे भी बड़ी बात है कि नीतियों के संबंध में जो सुझाव दिए गए उन पर काम भी किया गया और दस नई नीतियां बनाई गईं। इनमें कुछ नीतिया तो महाराष्ट्र व गुजरात में भी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में फूड प्रोसेसिंग की बहुत सम्भावनाएं हैं। एरोमा के द्वारा यहां के किसानों की आय काफी बढ़ाई जा सकती है। यहां के एरोमा को उत्तराखण्ड की खुशबु के तौर पर पहचान दिलाई जा सकती है।

डिक्सान टेक्नोलोजी के श्री सुनील वाचानी ने इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि समय आ गया है जब उत्तराखण्ड में निवेश के लिए उद्यमी आगे आएं। एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉ. असीम चौहान ने प्रदेश में स्कूल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट व रिसर्च में काम करने की इच्छा जताई। भेल के एमडी श्री अनिल सोबती ने कहा कि भेल का उत्तराखण्ड से गहरा नाता है। यहां का पॉलिसी फ्रेम वर्क, शानदार कनेक्टीवीटी, पर्याप्त स्किल, समृद्ध संस्कृति, राजनीतिक इच्छा शक्ति निवेश को प्रोत्साहित करते हैं। सीआईआई के श्री सचित जैन ने कहा कि उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहां इस प्रकार का इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, आयुक्त उद्योग श्रीमती सौजन्या सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री मंजीत नेगी द्वारा लिखित पुस्तक ''केदारनाथ से साक्षात्कार'' का विमोचन भी किया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–07(10/55)**

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट के दूसरे दिन सोमवार को एम.एस.एम.ई. सेशन के अन्तर्गत वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने निवेशकों का स्वागत करते हुए कहा कि एम.एस.एम.ई. का क्षेत्र उत्तराखण्ड में महत्वपूर्ण है। उन्होंने निवेशकों को राज्य में पूंजी निवेश करने के लिये प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के क्षेत्र में एक अच्छा माहौल बना हुआ है। हमारे पास कुशल मानव संसाधन, सस्ती बिजली व कानून व्यवस्था है। उद्योग के क्षेत्र में राज्य से बेहतर वातावरण देश में किसी अन्य राज्य में नही मिलेगा। राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास के क्षेत्र में 13800 बच्चों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने एक लाख बच्चों को प्रशिक्षित कर स्किल करने का लक्ष्य रखा है। पूंजी निवेश के माध्यम से एम.एस.एम.ई. को और बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है।

श्री पंत ने कहा कि राज्य में एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में निवेश आने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की काफी सम्भावनाएं हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है, ताकि उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इन्वेस्टर्स समिट के विभिन्न रोड़ शो के दौरान विभिन्न उद्यमियों व व्यापारिक संगठनों से मिले सुझावों को शामिल करते हुए दस नीतियां बनाई गईं। इनमें निवेश के अनुकूल प्राविधान किए गए हैं। मध्यम व लघु व्यवसायियों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। जीएसटी में छोटे व्यापारियों का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 20 लाख तक के टर्नओवर के उद्यमों को जीएसटी के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में एम.एस.एम.ई. के उद्योग सहित अन्य बडे व छोटे उद्योग भी स्थापित है। श्री पंत ने कहा कि निवेशक राज्य में पूंजी निवेश किस क्षेत्र में करें, इस हेतु हमने तीन प्रकार की श्रेणीयां बनाई है। उन्होंने कहा कि यदि उद्यमी पिथौरागढ़, चम्पावत, चमोली, उत्तरकाशी व हिमालय से लगे हुए क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करते है, तो भूमि खरीद में स्टॉम्प शुल्क में सब्सिडी दी जायेगी।

श्री पंत ने कहा कि प्रदेश में सड़क, रेल व वायु सेवा भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 800 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों तक रोड कनैक्टिविटि बेहतर है। 250 तक की आबादी वाले गावों को भी सड़क मार्ग से जोडा गया है। कर्णप्रयाग–ऋषिकेश रेल लाईन का कार्य भी गतिमान है। ऑल वेदर रोड का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। ऑल वेदर रोड का कार्य पूर्ण होने के बाद सड़क कनैक्टिविटि और भी बेहतर होगी, जिससे आवागमन को और अच्छी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमारी रोड कनैक्टिविटि बेहतर है, हम देश के बडे शहरों से जुड चुके है। उन्होंने कहा कि हमारी हवाई सेवा भी बेहतर है। देश के प्रमुख शहरों के लिये जौलीग्रांट एयरपोर्ट से हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही है। जबकि प्रदेश में देहरादून से पंतनगर तक हवाई सेवा भी शुरू की गई है। इसके साथ ही आज उडान योजना के अन्तर्गत देहरादून से नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ तक भी हवाई सेवा शुरू की जा चुकी है। इस अवसर पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित विभिन्न एमओयू हस्ताक्षरित किये गये।

इस अवसर पर अपर सचिव भारत सरकार श्री राममोहन मिश्रा, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, महानिदेशक/आयुक्त उद्योग श्रीमती सौजन्या, उद्योग समूह के प्रतिनिधियों, विषय विशेषज्ञों, बैंकर्स सहित अन्य गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–06(10/54)**

इन्वेस्टर्स समिट–2018 के दूसरे दिन हेल्थ केयर एण्ड वैलनेस सेशन में केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अष्वनी कुमार चौबे ने कहा कि उत्तराखण्ड में धार्मिक पर्यटन, योगा, ध्यान केन्द्र, पंचकर्म, नेचुरलपैथी आदि के क्षेत्र में निवेष की पर्याप्त संभावनाएं हैं। प्रदेष के ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए आकर्षक होंगे तथा योगाभ्यास के लिए ऋषिकेष एवं हरिद्वार के साथ अन्य पर्यटक स्थलों को पसंद करेंगे। उन्होंने कहा कि निवेषक राज्य में पर्यटन एवं योगा केन्द्र अवस्थापना विकास में बेहिचक अधिकाधिक रूचि दिखायें। उन्होंने कहा कि राज्य के नैसर्गिक सौन्दर्य और आध्यात्मिक स्वरूप और भयमुक्त वातावरण को देखते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेष कर अपनी महति भूमिका निभायें। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी और अन्य जनपदों में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का निर्माण किया जा रहा है तथा राज्य में सिंगल विण्डों के माध्यम से निवेष के लिए बेहतरीय माहौल बनाया गया है। उन्होंने आनंदा, पतंजलि के साथ–साथ अन्य निवेषकों को भी आयुष, पंचकर्मा, योगा, मसाज आदि चिकित्सा के क्षेत्र में आगे आने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अच्छे निवेष हेतु राज्य द्वारा कई क्षेत्रों में षिथिलीकरण भी कर दिया गया है और बेहतर निवेष हेतु सब्सिडी की सहायता भी निवेषकों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की चिकित्सा हेतु बीमा किया गया है साथ ही 1300 करोड़ रूपये की धनराषि का प्राविधान विलनेष सेन्टरों के लिए किया है तथा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में भी धनराषि का प्राविधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के संचालन के लिए आरोग्य मित्रों का भी रखा गया है।

प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि आयुर्वेद के क्षेत्र में अभी तक 3 हजार करोड़ का एमओयू हो चुका है और आगे आने वाली समय में बड़े निवेष की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में निवेष हेतु सभी परेषानियों को दूर किया जा रहा है जिसके लिए एकल खिड़की की व्यवस्था की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस समिट को देखते हुए राज्य के कई आयुर्वेदिक विद्यालयों ने आगामी सत्र से नेचुरल पैथोलाजी, ईष्पा, मसाज, योगा आदि पर नये विषयों को खोलने तथा उच्च स्तर पर कक्षायें संचालित करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि ब्रांडेड ग्रुपों द्वारा अच्छे निवेष की संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक क्षेत्र में 40 प्रतिषत दवायें निर्मित की जा रही है और बड़े निवेष से राज्य में आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में तेजी आयेगी और लोगों को रोजगार के साधन मुहय्या हो सकेंगे। उन्होंने निवेषकों को आयुर्वेद के क्षेत्र में राज्य में निवेष करने के लिए आमंत्रित किया।

सचिव, उत्तराखण्ड आरके सुधांषु ने कहा कि उत्तराखण्ड विगत कई वर्षो से आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के क्षेत्र में अग्रसर है और राज्य में बेहतर निवेष की संभावनाओं को देखते हुए इस क्षेत्र में निवेष के लिए निवेषकों को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं को देखते हुए कई प्रकार की छूट भी प्रदान की जा रही है। निवेषक सम्मेलन में आचार्य बालकृष्ण ने निवेषकों को निवेष हेतु आमंत्रित किया और कहा कि उत्तराखंड आयुर्वेद के क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं समेटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां दक्ष मानव संसाधन व उद्योग का बेहतर माहौल है और इस क्षेत्र में निवेष की आवष्कता है।

इस अवसर पर महेष नटराजन, सौम्यजीत राय, प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार, रंजीत मेहता, डा.विजय धस्माना आदि ने भी संबोधित किया।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–05(10/53)**

इन्वेस्टर समिट के द्वितीय सत्र में प्लेनरी सेशन ऑन उद्यमिता विकास एंड स्टार्ट–अप्स के विषय में आयोजित सत्र की अध्यक्षता करते हुए वित्त, संसदीय मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य ने स्टार्ट–अप के क्षेत्र मे आगे बढने हेतु 2018 स्टार्ट–अप नीति बनाई है जिसके तहत राज्य के नव युवकों को अवसर प्रदान किया जा रहा है। नीति के तहत स्टार्ट–अप स्थापित करने के लिए नए उद्यमियों को पूंजीगत लाभ, बिजली में रियायत के साथ ही अन्य सुविधायें प्रदान की जा रही है। घर बैठे ही आवेदक ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से पंजीकरण कर सकते है। स्टार्ट–अप के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्यमियों को उत्तराखण्ड पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एड उद्योग द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रयास है के राज्य के प्रति जिले में औद्योगिक आस्थान स्थापित किये जाए। राज्य की नई प्रतिभाओ के सृजनात्मक एवं नवाचार विचार, सोच के लिए पूर्ण रूप से सहयोग किया जाएगा।

महानिदेशक/आयुक्त उद्योग श्रीमती सौजन्या ने कहा कि स्टार्ट–अप योजना राज्य के फलैगशिप प्रोग्राम के अन्तर्गत है। इसके लिए सरकार द्वारा विशेष पहल की गई है। लोगों में योजना की जागरूकता हेतु स्टार्ट–अप यात्रा निकाली गई थी। युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार बढाने के लिए कई तरह की रियायते दी जा रही है। स्टार्ट–अप शुरू करने वाले सामान्य युवाओं को एक साल तक प्रतिमाह 10 हजार रूपये जबकि पहाड के युवाओं के साथ ही महिलाओं, एस.सी., एस.टी को प्रतिमाह 15 हजार मिलेंगे। स्टार्ट–अप के तहत स्थापित हुए उद्योगों को एसजीएसटी में तीन साल तक छूट मिलेगी। प्रोडेक्ट की मार्केटिंग भी योजना में शामिल है। स्टार्ट–अप नीति के तहत राज्य का कोई भी युवा अपना आईडिया के आधार पर उद्योग की स्थापना कर सकता है। स्टार्ट–अप योजना ने लोगों के जीवन को आसान कर दिया है व अधिक से अधिक लोग योजना का लाभ मिल सके इसके लिए आवश्यकतानुसार समय–समय में नीति में संशोधन भी किया जाएगा।

पी.एच.डी चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड उद्योग से आए हुए पैनलिस्ट के सदस्यों ने राज्य में स्टार्ट–अप योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने सुझाव दिए। कहा कि स्टार्ट–अप योजना को शुरू करने में सफलता व विफलता में से कुछ भी हासिल हो सकता है किन्तु दृढ निश्चय होकर अपने कार्य में सभी उद्यमी लगे रहे। विफलता जीवन का अंग है व विफलताओं से मनुष्य को सीखने को मिलता है। ओयो, फिल्पकार्ट जैसे आइकन के विषय में कहा कि से सभी कम्पनी अपनी सफलता से पूर्व कई चरणों में विफल हुई थी किन्तु अंत में आज देश की नामी कम्पनियों में शुमार है। हमारा लक्ष्य है 2025 तक 100 यूनिकॉन स्थापित करना है, इस समिट में आए हुए प्रतिभागियों से उम्मीद है कि कुछ यूनिकॉन उत्तराखण्ड से निकलकर सामने आएगे। इस अवसर पर पैनलिस्ट ने आए हुए प्रतिभागियों की क्वेरियों के उत्तर भी दिए।

इस अवसर पर पीएचडी चैम्बर्स के अध्यक्ष वीरेन्द्र कालरा, टी–हब के फाउण्डर श्रीनिवास कोलीपारा, वेन्चर कैपिटलिस्ट के अध्यक्ष एवं फाउण्डर डॉ अपूर्व रंजन, पेटीएम के वाइस प्रसिडेंट सौरभ जैन, इन्वेस्टमेंट बैंकस आशीष अगवाल, अंशुमन खन्ना सहित प्रतिभागी उपस्थित थे।

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–04(10/52)**

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को उड़ान योजना अन्तर्गत जौलीग्रांट एयरपोर्ट से नैनीसैनी, पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा की ट्रायल लैंडिंग को संयुक्त रूप से फ्लैग ऑफ किया। गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति तथा प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों तक हवाई सेवाओं का विस्तार राज्य एवं देश के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास आवागमन को भी सुविधाजनक बनाते हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस हवाई सेवा के आरम्भ होने से गढ़वाल व कुमाऊँ को हवाई सेवा से जोड़ने में मदद मिलेगी तथा पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आवागमन को और अधिक सुगम बनाने के लिए जल्द ही उड़ान योजना के तहत अन्य हवाई सेवाएं भी शुरू की जायेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड इन्वेस्टर समिट में निवेशकों ने राज्य में सस्ती हवाई सेवाएं संचालित करने में भी रूचि दिखाई है। शीघ्र ही राज्य में हवाई सेवाओं का विस्तार धरातल पर दिखाई देने लगेगा।

इस हवाई सेवा से जौलीग्रांट से नैनीसैनी के लिए केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टमटा, सांसद भगत सिंह कोश्यारी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री धन सिंह रावत व विधायक पुष्कर सिंह धामी रवाना हुए।

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत, पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, सांसद श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक', भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, विधायक श्री हरवंश कपूर, श्री मुन्ना सिंह चौहान, सुरेश राठौर, श्री गोपाल सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–03(10/51)**

इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन शिक्षा एवं कौशल विकास सत्र को सम्बोधित करते हुए शिक्षा मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा कि स्वस्थ्य शरीर–मस्तिष्क से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। उत्तराखण्ड में प्राकृतिक सौन्दर्य के साथ ही अनुकूल वातावरण है इसलिये निवेशक आयें व शिक्षा के क्षेत्र में निवेश कर सहभागी बनें।

शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सफल प्रयोग किये जा रहे हैं। आज के दौर में शिक्षा के माध्यम से डिजीटल एवं फिजीकल को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिससे युवा रोजगार एवं स्वरोजगार से सीधे जुड़ सकें। उच्च शिक्षा के साथ ही विद्यालयी शिक्षा को रोजगारपरक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ ही मॉडल स्कूलों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड संस्कृति की जननी है, तकनीकी शिक्षा के साथ ही संस्कृत, योग शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश के 13 जनपदों में संचालित राजीव गांधी आवासीय विद्यालय को पीपीपी मोड में चलाने हेतु, पहाड़ी क्षेत्रों में निजी आवासीय विद्यालय संचालित करने तथा युवाओं को खेल से जोड़ने हेतु खेल अकादमी खोलने के लिए निवेशकों को आमंत्रित किया। उन्होंने देवभूमि उत्तराखण्ड को ज्ञान भूमि बनाने में सहयोग की अपील भी की।

सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता, भारत सरकार, डॉ0 के.पी. कृष्णन ने कहा कि भारत सरकार द्वारा युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु कौशल विकास मंत्रालय बनाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत पूरे भारत में कौशल विकास केन्द्र चलाये जा रहे हैं, जिसके माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित कर सीधे रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा व उद्योगों में समन्वय स्थापित करें ताकि उद्योगों की मांग के अनुसार युवाओं को तैयार कर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि बेहतर तकनीकी शिक्षा हेतु बेहतर शिक्षा व शिक्षण संस्थान देने हेतु भारत सरकार पूर्ण सहयोग करेगी।

कार्यक्रम को शिक्षा सचिव डॉ. भूपेन्द्र कौर औलख, अपर सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास डॉ. अहमद इकबाल, कुलपति एमीटी विश्वविद्यालय, डॉ. असीम चौहान, अम्बरीश दत्त, अनीता राजन, कुमार गुरू आदि द्वारा भी सम्बोधित किया गया।

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(10/50)**

उत्तराखण्ड इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन कृषि व होल्टिकल्चर के क्षेत्र में निवेश करने हेतु कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कृषि व होल्टिकल्चर के क्षेत्र में 4834 करोड का एम ओ यू साइन हुआ है। जिसके अन्तर्गत 1325 करोड का एरोमा सेक्टर आगर्निक खेती हेतु 1309 करोड व 2200 करोड हाल्टिकलचर के क्षेत्र में एमओयू हुआ है। उन्होंने बताया कि रसना द्वारा 500 करोड का निवेश राज्य में किया जा रहा है। उन्होने कहा कि भारत में 42 फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, जिसमें से 2 उत्तराखण्ड में स्थापित है। उन्होने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग हेतु नौथा में सेक्टर स्थापित किया रहा है जिसमें 500 लोगो को रोजगार प्राप्त होगा। उन्होने कहा वर्तमान में उत्तराखण्ड में 300 हेक्टेयर भूमि में चाय की खेती की जा रही है। इसे बढाकर 1300 हेक्टेयर किया जायेगा। उन्होने बताया कि अर्जेटिना हर्बल के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में निवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा कि आर्गनिक खेती बढाने के लिए अलग–अलग क्लस्टर बना कर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार किसानों को उनके उत्पादों का अच्छा मूल्य दिलाने के लिए 200 हेक्टियर से 400 हेक्टेयर तक एक ही तरह का उत्पाद पैदा कराया जायेगा। उन्होने कहा कि वर्तमान में उत्ताखण्ड में 24 कोल्ड चैन स्थापित किये गये हैं। जिसमें 15 कोल्ड चैन डेढ़ वर्ष के अन्तर्गत स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1 लाख एकड़ में आर्गेनिक खेती की जा रही है। अगले वर्ष तक इसे बढ़ाकर 3 लाख एकड़ में किया जायेगा।

राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। पशुपालन से उनकी आर्थिकी में उन्नति होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालन के माध्यम से जैविक खेती संभव है। उन्होंने कहा पशुधन उत्पाद हमारे आजीविका का महत्वपूर्ण अंग है। इस क्षेत्र में निवेशकों की अत्यधिक मांग है। उन्होंने कहा पशुपालन को बढ़ावा देने व उन्नतशील नस्ल के पशुओं हेतु प्रदेश में सीमेन लैब बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि चारे के क्षेत्र में हम 36 प्रतिशत की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए निवेशक व्यवसायिक माडल तैयार कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते हुए मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मशरूम आदि क्षेत्रों में आगे आयें।

संयुक्त सचिव खाद्य एवं प्रसंस्करण, भारत सरकार श्री पराग गुप्ता ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। हम सब पहले से ही फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। आज यह नई तकनीकी के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा क्लटर बनायें व उसमें फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगायें।

केन्द्रीय मंत्री, खाद्य व प्रसंस्करण, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने कहा उत्तराखण्ड में पूरा हिन्दुस्तान समाया हुआ है। यह देवभूमि है, ऋषिमुनियों ने यहां जप और तप किया है। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत करता है, किन्तु बुनियादी सुविधायें न होने से अनाज की बर्बादी होती है। इसके लिये किसानों को मूलभूत सुविधा देनी होगी। उन्होंने कहा देवभूमि में फूड प्रोसेसिंग की अपार संभावनाऐं हैं।

इस अवसर पर सचिव डॉ. आर.मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा निवेशकों को अनेक जानकारियां उपलब्ध कराई तथा राबो इक्विटी एडवाईजर के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री राजेश श्रीवास्तव, पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवीन्द्र चौधरी, आनन्द डेयरी के चेयरमैन श्री राधेश्याम दीक्षित तथा फ्रिक इंडिया के प्रबन्ध निदेशक, जसमोहन सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

देहरादून 08 अक्टूबर, 2018 (सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(10/49)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में आयोजित डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट 2018 के दूसरे दिन थीम पवेलियन व प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी प्रतिभागियों व निवेशको से उनके प्रोजेक्ट व प्रस्तावो की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार सभी प्रतिभागियों व निवेशको को हर संभव सहयोग तथा सहायता देने के लिए तत्पर है।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग